

प्रेषक,

एमोएच० खान,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,  
उत्तराखण्ड जल संस्थान,  
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 15 जून, 2009

विषय : राज्य योजना के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में रिसावदार कुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 171/उन्तीस(2)/09-22(14पे0)/2008 दिनांक 24.03.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के 10 जनपदों हेतु कुल 100 इन्फिल्ड्रेशन वैल टाइप हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु टी०ए०सी० के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रु० 96.76 लाख की धनराशि के सापेक्ष रु० 53.37 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवशेष धनराशि रु० 43.39 लाख (रुपये तेतालीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नशर्तानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. स्वीकृत किये जा रहे रिसावदार कुओं के निर्माण के लिए स्थल चयन करते समय जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन न हो।

4. उक्त रिसावदार कुओं का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में ही किया जायेगा जहाँ सड़के नहीं हैं और हैण्डपम्प नहीं लगाये जा सकते हैं। विभाग इस हेतु आवश्यक मानक आदि बनाकर प्रत्येक जनपद में ऐसे स्थानों का चयन करने के बाद उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन लेकर ही स्वीकृति की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण करेंगे।

5. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तराखण्ड शासन के वित्त (वी०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सेन्टेज चार्जज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमत्य नहीं होगी। कृपया इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर आगणन में सेन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

6. कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। स्वीकृत कार्य के विपरित भुगतान कार्य की वास्तविक आय के अनुसार ही सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

8. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी राशि स्वीकृत की गयी है।

9. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

10. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

11. निर्माण सामग्री क्रय रिसावदार कुओं का निर्माण कराने से पूर्व एवं कार्य करते समय उत्तराखण्ड अधिग्राहित नियमावली, 2008 के समस्त नियमों का मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय और उक्तानुसार टैप्डर में चयनित निर्माण एजेन्सी द्वारा ही उक्त कार्य निष्पादित किया जायेगा।

12. कार्य कराने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली-भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

13. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

14. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-“2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत- 102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम-04-जल श्रोतों का रखरखाव तथा पुर्नजीवन-00-20-सहायक अनुदान/अंशादान/राज सहायता” के नामे डाला जायेगा।

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 29/XXVII (2)/2009 दिनांक 02 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

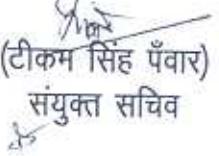
(एम०एच० खान)  
सचिव

पृ०सं० ६०९(०) /उन्तीस (2) /०९-२(१४प०) /२००८ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ।
3. जिलाधिकारी, टिहरी / पौडी / रुद्रप्रयाग / अल्मोड़ा / नैनीताल एवं पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2 / वित्त (बजट सैल) / नियोजन प्रकोष्ठ।
7. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री जी को मा० पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड शासन।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
  
(टीकम सिंह पावार)  
संयुक्त सचिव